Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

45 आईएएस अधिकारियों पर सालों से लंबित शिकायती प्रकरणों की होगी जांच, हाईकोर्ट में पीआईएल दायर।

याचिकाकर्ता का कहना : सरकार 15 साल में भी नहीं ले पाई निष्पक्ष जांच का निर्णय।

क्रांति समय दैनिक समाचार

चिरमिरी। राज्य के 45 आईएएस अधिकारियों कि मुश्किल है अब बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल इन अधिकारियों के खिलाफ 10 से 15 साल पहले की गई शिकायतें आज भी लंबित है। उन शिकायतों पर निष्पक्ष जांच कराने के लिए आरटीआई विशेषज्ञ राजकुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका 69/2021 दाखिल की है। वही मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ हुई शिकायतों की विस्तृत जानकारी मांगी है।

बता दें कि, प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से शिकायती प्रकरण बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। दिसंबर 2015 में विधानसभा में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों पर प्रश्न पूछा गया था। जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 तक 45 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती प्रकरण लंबित होने की बात कही थी। जिसके बाद से आरटीआई विशेषज्ञ राजकुमार मिश्रा ने मामले में आरटीआई से जानकारी जुटाना शुरू किया। साथ ही 2021 में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों की निष्पक्ष जांच के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट में डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान आईएएस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की विस्तृत जानकारी मांगी है। जिस पर याचिकाकर्ता ने जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जल्द ही मामले में कोई नया मोड़ आएगा।

आई.ए.एस. अधिकारियों के विरुद्ध लंबित शिकायत

स.क्र.	अधिकारी का नाम / पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना
1.	श्री सी.के. खैतान, तत्कालीन सचिव, जल संसाधन विभाग	सयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
2.	श्री जी. आर. चुरेन्द्र, तत्का. अपर कलेक्टर गरियाबंद	कलेक्टर, सूरजपुर
3.	श्री छत्तर सिंह डहरे, सयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा विभाग	संयुक्त सचिव, धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग
4.	डॉ कमलप्रीत सिंह, तत्का. संचालक, स्वास्थ्य विभाग	संचालक, संस्थागत वित्त (विशेष सचिव, वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार)
5.	श्री मुकेश बंसल, रायगढ़ कलेक्टर	कलेक्टर, राजनांदगांव
6.	श्री एन.एम. क्षीरसागर, अनु.अधि. सारंगढ़	अपर आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा छ.ग. रायपुर)
7.	श्रीमती शारदा वर्मा, तत्का. अपर संचालक, आदिम जाति	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार
8.	श्रीमती ऋतु सेन, कलेक्टर सरगुजा	कलेक्टर, सरगुजा
9.	श्री निरंजन दास, कलेक्टर, गरियाबंद	कलेक्टर, गरियाबंद
10.	श्री हिमशिखर गुप्ता, तत्का. कलेक्टर, जशपुर	कलेक्टर, जशपुर
11.	श्री एन.के. खाखा, तत्का. आयुक्त आदिम जाति तथा अनु. जनजाति विभाग	सदस्य राजस्व मंडल, बिलासपुर
12.	श्री उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर, महासमुंद	कलेक्टर, महासमुंद
13.	श्री ओ.पी. चौधरी, कलेक्टर, जांजगीर चांपा	कलेक्टर, जांजगीर चांपा
14.	श्रीमती आर. संगीता, कलेक्टर, दुर्ग	कलेक्टर, दुर्ग
15.	श्री टी. राधाकृष्णन, संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	संचालक, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर
16.	श्री अमित कटारिया, कलेक्टर रायगढ़	कलेक्टर, बस्तर
17.	श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, कलेक्टर, बालोद	संचालक, कृषि विपणन मंडी बोर्ड
18.	श्री एलेक्स पाल. मेनन, कलेक्टर, सुकमा	कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज
19.	श्री के.सी. देवासेनापति, कलेक्टर, दंतेवाड़ा	कलेक्टर, जिला – दंतेवाड़ा
20.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल, आयुक्त, रायपुर सभाग	आयुक्त, रायपुर संभाग तथा आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार
21.	सुश्री ओमेगा युनाईस टोप्पो, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग	संयुक्त सचिव, वन
22	श्री भीमसिंह, तत्का. अनु.अधिकारी, पंड्रारोड	कलेक्टर, धमतरी
23	श्री चंदन कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर
24	सुश्री अलरमेलमंगई डी. कलेक्टर जिला रायगढ़	कलेक्टर, रायगढ़
25	श्री रणबीर शर्मा,एसडीएम भानुप्रतापपुर	अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
26	श्री जी.एस. मिश्रा, आबकारी आयुक्त	आयुक्त, आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यकर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग, तथा प्रबंध संचालक, वेवरेजेस कार्पोरेशन तथा सचिव, जनसंपर्क
27	श्री विलास संदीपन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा

147 [16 दिसम्बर, 2015

28	श्री अवनीश कुमार शरण, आयुक्त नगर निगम रायपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर
29	डॉ सारांश मित्तर, आयुक्त नगर निगम	आयुक्त, नगर निगम, रायपुर
30	श्री जे.पी. पाठक, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
31	श्री अंकित आनंद, तत्का. कलेक्टर जशपुर	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी
32.	श्री दिनेश श्रीवास्तव, तत्का. प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मंडल, रायपुर	सचिव, महिला एवं बाल विकासतथा सचिव, सामाज कल्याण विभाग तथा सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
33.	श्री टामन सिंह सोनवानी, तत्का सीईओ, जिला पंचायत जांजगीर चांपा	कलेक्टर, नारायणपुर
34.	श्री के.डी.पी. राव, अध्यक्ष छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर	अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर
35.	श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, तत्का. प्रबंध संचालक, मार्कफेड	आयुक्त-सह-संचालक, पंचायत
36.	श्री एम.के. राउत, तत्का. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग, विकास आयुक्त
37.	श्री अन्बलगन.पी., कलेक्टर, बस्तर	कलेक्टर, बिलासपुर
38.	श्री व्ही. के. धुर्वे, कलेक्टर, कोण्डागांव	संयुक्त सचिव, जेल/परिवहन विभाग मंत्रालय
39.	श्री रजत कुमार, कलेक्टर, जिला कोरबा	सयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री व संयुक्त सचिव, विमानन तथा संचालक, विमानन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण
40.	श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, कलेक्टर राजनांदगांव	आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, अतिरिक्त प्रभार आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
41.	डॉ. रोहित यादव, तत्का. कलेक्टर, राजनांदगांव	संचालक, नगरीय प्रशासन विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. सड़क विकास निगम
42.	श्री भुवनेश यादव, तत्का. संचालक, उद्यानिकी विभाग	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा मिशन संचालक राष्ट्रीय उच्चर शिक्षा अभियान का अतिरिक्त प्रभार
43.	श्री सुव्रत साहू, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
44.	श्री अमृत खलको, कलेक्टर, बालोद	अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग,
45.	श्री दिलीप वासनिकर, तत्का. नगर निगम आयुक्त, दुर्ग	आयुक्त बस्तर संभाग, जगदलपुर

15 साल में भी नहीं ले पाए जांच का निर्णय : राजकुमार मिश्रा

मामले में आरटीआई विशेषज्ञ राजकुमार मिश्रा का कहना है कि, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल ४५ आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर शिकायती प्रकरण १०, १२ या १५ साल से लंबित है। क्या कांग्रेस सरकार और क्या भाजपा सरकार कोई भी यह निर्णय नहीं कर पाई की इन शिकायती प्रकरणों पर जांच करनी है या नहीं करनी। मामले में मैंने जानकारी जुटाकर माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में जनहित याचिका लगाई है। सुनवाई के दौरान डबल बेंच ने आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जानकारी भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। जल्द ही दस्तावेज इकट्ठा कर हाई कोर्ट में पेश करूंगा।

राजस्व तथा खाद्य विभाग के 2492 पदों पर भर्ती के लिए तैयारियां शुरू..

क्रांति समय दैनिक समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह (पुलिस), राजस्व तथा खाद्य विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अनुमति जारी करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उनके इस निर्देश के बाद कुल 2492 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरुकर दी गई

है। श्री बघेल ने इन विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज लिए गए निर्णय के फलस्वरूप गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत ' बस्तर फाइटर्स ' बल के गठन की मंजूरी जारी की गयी जिसमें 2100 पदों के भर्ती की अनुमति दी गयी है। इसी तरह राजस्व विभाग अंतर्गत मैदानी स्तर पर 301 पटवारियों के पदों पर नयी भर्ती की जाने की अनुमति दी गई है । खाद्य विभाग अंतर्गत 84 खाद्य निरीक्षकों के साथ-साथ कुल 91 पदों पर भर्ती की की जाएगी ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी मेहनत और लगन के साथ तैयारियां करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को रिक्त पदों का परीक्षण कर उन पर सीधी भर्ती किए जाने की कार्ययोजना बना कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया को त्वरित गति एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

संकट के बावजूद राज्य सरकार लगातार युवाओं सहित सभी वर्ग के प्रदेशवासियों के हित में निर्णय ले रही है। बस्तर फाइटर्स दल के गठन से जहां बस्तर के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं स्थानीय युवाओं के अनुभवों का लाभ पुलिस बल को भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पटवारियों की भर्ती होने से किसानों एवं नागरिकों की राजस्व प्रशासन से संबंधित समस्याओं एवं मांगों का त्वरित निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सकेगा। खाद्य निरीक्षकों की भर्ती होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा।

भर्ती की अनुमति जारी होते ही भर्ती विज्ञापन एवं परीक्षा आयोजन की कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि कोविड संक्रमण के कारण उत्पन्न विषम आर्थिक

नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक मीणा ने ली पुलिस अधिकारियों और थानेदारों की बैठक

क्रांति समय दैनिक समाचार

भिलाई (एजेंसी)। दुर्ग जिले के नव पदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा के द्वारा पुलिस कंट्रौल रूम भिलाई के सभागार में दुर्ग पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकरियो, थाना एंव चौकी प्रभारियो की पहली बैठक ली। बैठक में नव पदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा समस्त अधिकारियो का परिचय प्राप्त किया गया। उसके बाद बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियो को जिले में जुए, सट्टे एंव अवैध व्यापार करने वालो पर पूर्ण अकुंश लगाने के सख्त निर्देश दिये। जनता से सद्भावनापूर्वक व्यवहार करने एंव उनकी समस्या का जल्द निराकरण करने के संबंध मे आवश्यक निर्देश भी दिये। थानो के रिकार्ड दुरूस्त रखने, शिकायत/आवेदन की जांच एंव निराकरण समय पर करने, माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त वारंटो/पत्रो का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तामीली रिपोर्ट भेजने से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिये।

जुआ, सट्टा और अवैध व्यापार करने वालो पर पूर्ण अकुंश लगाने दिये सख्त निर्देश

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार धुरव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण लखन साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात कविलाश टंडन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्लू श्रीमती मीता पवार, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर राकेश जोशी, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी विश्वास चंद्राकर, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग कौशलेन्द्र पटेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन देवांश सिंह, उप पुलिस अधीक्षक यातायात गुरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अभिषेक झा, रक्षित निरीक्षक दुर्ग निलेश द्विवेदी सहित इनके साथ जिले के समस्त अराजपत्रित अधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा जिले में 30 सितंबर तक च्वाइस सेंटर में बनेंगे निशुल्क

क्रांति समय दैनिक समाचार

कोरबा (एजेंसी) कोरबा जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 सितंबर तक नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे है। पात्र राशन कार्ड धारी परिवारों को पांच लाख तक की नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। शेष राशन कार्ड धारी परिवार कार्ड से पचास हजार रूपये तक की नि:शुल्क इलाज करा सकेंगे। पात्र हितग्राही

पचास हजार से पाँच लाख तक मिलेगी नि:शुल्क इलाज की सुविधा

साढ़े पाँच लाख से अधिक हितग्राहियों ने बनवाया आयुष्मान कार्ड

हितग्राही अपने नजदीकी चॉइस सेंटर कॉमन सर्विस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। जिले में अब तक 5 लाख 81 हजार हितग्राहियों का राशन कार्ड बनाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने छूटे हुए हितग्राहियों को तय समय सीमा में आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अंत्योदय, प्राथमिकता अपना इलाज पंजीकृत सरकारी या निजी अस्पतालों में करा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए च्वाइस सेंटरों या कामन सर्विस सेंटरों से यदि पैसे की मांग की जाती है, तो हितग्राही इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 104 या 1455 में कर सकते हैं। हितग्राही स्वयं सीएमएचओ कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार
में प्रेसनोट,नोटिस,वेपार
संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com

समस्या आपकी हमें भेजे

अपने क्षेत्र में समस्याएं
हमें लिखे या बताएँ
और समस्याएं का हल
संबंधित विभाग से मिलेगा
मोबाईल:-987914180
या फोटा,वीडियो हमें भेजे

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार
भारत के अन्य राज्यों में जिला ब्यूरों
और अन्य शहर,ग्राम में पत्रकारों
की नियुक्त के लिए आवेदन कर सकते है
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com